गरीबों की मौज! 21 हजार परिवारों को मिलेगा फ्री आवास और पेंशन

विषय सूची (Table of Contents):

>> जीरो पावर्टी योजना उन्नाव के 21 हजार से ज्यादा गरीब परिवारों के लिए बनी वरदान...
>> गांव-गांव तक पहुंचा सरकारी योजनाओं का लाभ...
>> दो चरणों में हुआ सत्यापन 25 हजार में से 21,523 परिवार ही मिले असली पात्र...
>> अपात्रों की हुई छंटनी, बनी फाइनल लिस्ट (List 2026)...
>> 60 पार के बुजुर्गों को बड़ी राहत अब शत-प्रतिशत को मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन...
>> खाते में सीधे पहुंचेगी पेंशन की राशि...
>> बेघर और अति निर्धन परिवारों को मिलेगा अपना पक्का आशियाना...
>> आवास निर्माण के लिए जारी होगी किस्त...
>> आयुष्मान कार्ड की स्थिति 70 प्रतिशत को मिला लाभ, 30 फीसदी परिवार अभी भी वंचित...
>> बाकी 30 के लिए विशेष शिविर का आयोजन...
>> वित्तीय वर्ष 2025-26 की तैयारी शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने में जुटा प्रशासन...
>> समयबद्धता पर अधिकारियों का जोर...
>> डीपीआरओ का बयान सभी चिन्हित लाभार्थियों को तय समय में मिलेगा उनका हक...
>> प्रक्रिया को बनाया जा रहा है आसान...
>> अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)...

जीरो पावर्टी योजना: उन्नाव के 21 हजार से ज्यादा गरीब परिवारो

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले मेंजीरो पावर्टी योजना (Zero Poverty Scheme)गरीब और असहाय परिवारों के लिए एक नई उम्मीद बनकर सामने आई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन लोगों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है जो पात्रता रखने के बावजूद अब तक लाभ से वंचित थे।

प्रशासन द्वारा चलाए गए इस विशेष अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले गरीब परिवारों को चिह्नित कर उन्हें बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। लेटेस्ट अपडेट (Latest Update 2026) के अनुसार, हजारों परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है।

इस योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से आवास, वृद्धावस्था पेंशन और स्वास्थ्य सुविधाओं (आयुष्मान कार्ड) पर फोकस किया गया है। स्थानीय प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि कोई भी वास्तविक और पात्र लाभार्थी इन सुविधाओं से अछूता न रहे।

गांव-गांव तक पहुंचा सरकारी योजनाओं का लाभ

जीरो पावर्टी योजना केवल एक घोषणा नहीं, बल्कि एक जमीनी हकीकत बन चुकी है। उन्नाव जिले के ग्रामीण इलाकों में इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। जो बुजुर्ग और बेघर परिवार अब तक दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे, उन्हें अब घर बैठे उनके अधिकार मिल रहे हैं।

लाभार्थियों का स्टेटस चेक (Status Check) करने के लिए ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने पर खास जोर दिया गया है, ताकि किसी भी अपात्र व्यक्ति को इसका फायदा न मिल सके।

यह भी पढ़ें:भारत में मुफ्त योजनाओं का सूरज! जानिए कौन-कौन लोग मिलाएंगे 5 लाख तक का इलाच

दो चरणों में हुआ सत्यापन: 25 हजार में से 21,523 परिवार ही मि

जीरो पावर्टी योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान करना एक बड़ी चुनौती थी। इसके लिए प्रशासन ने जनपद की 1037 ग्राम पंचायतों में एक व्यापक सर्वे अभियान चलाया। हर ग्राम पंचायत से न्यूनतम 15 और अधिकतम 25 परिवारों को चिह्नित करने का लक्ष्य रखा गया था।

इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सत्यापन दो अलग-अलग चरणों में पूरा किया गया। प्रथम चरण के सर्वे में कुल 25,925 गरीब ग्रामीण परिवारों का नाम शामिल किया गया था, जिन्हें संभावित लाभार्थी माना गया था।

अपात्रों की हुई छंटनी, बनी फाइनल लिस्ट (List 2026)

सर्वे रिपोर्ट तैयार होने के बाद जमीनी स्तर पर क्रॉस-चेकिंग की गई। इस कड़ी जांच और भौतिक सत्यापन के बाद पाया गया कि कई नाम अपात्रों के थे। अंततः छंटनी के बाद केवल 21,523 परिवार ही योजना के लिए वास्तविक पात्र पाए गए।

शासन का स्पष्ट निर्देश था कि केवल हकदारों को ही योजना का पैसा और लाभ दिया जाए। अब इन 21,523 परिवारों की फाइनल सूची तैयार कर ली गई है, जिसे ऑनलाइन पोर्टल पर भी अपडेट किया जा रहा है। आप अपने ग्राम प्रधान के माध्यम से भी यह लिस्ट पीडीएफ (PDF) फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं।

60 पार के बुजुर्गों को बड़ी राहत: अब शत-प्रतिशत को मिलेगी वृ

इस योजना की सबसे बड़ी सफलता बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन देने में है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से ऐसे बुजुर्ग थे जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी थी, लेकिन किसी कारणवश उनका नाम वृद्धावस्था पेंशन योजना में नहीं जुड़ पाया था।

जीरो पावर्टी सर्वे के दौरान ऐसे तमाम बुजुर्गों की पहचान की गई जो पूरी तरह से पात्र थे लेकिन पेंशन से वंचित थे। अब इन सभी बुजुर्गों का डेटा पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई (Apply Online) की तर्ज पर अपडेट कर दिया गया है।

खाते में सीधे पहुंचेगी पेंशन की राशि

प्रशासन ने वृद्धावस्था पेंशन को लेकर शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने का दावा किया है। अब इन बुजुर्गों को पेंशन मिलने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। जल्द ही डीबीटी (DBT) के माध्यम से इनके बैंक खातों में पेंशन की धनराशि ट्रांसफर की जाएगी।

बुजुर्गों के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि अब उन्हें अपनी छोटी-मोटी जरूरतों के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अधिकारियों द्वारा पेंशन भुगतान की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है।

यह भी पढ़ें:बिना गारंटी 5 करोड़ तक लोन! सरकार की नई बिजिनेस योजनाएं

बेघर और अति निर्धन परिवारों को मिलेगा अपना पक्का आशियाना

रोटी और कपड़े के साथ-साथ मकान इंसान की सबसे बड़ी मूलभूत आवश्यकता है। जीरो पावर्टी योजना के तहत उन्नाव में ऐसे अति निर्धन और आवासहीन परिवारों की भी पहचान की गई है, जिनके पास सिर छिपाने के लिए अपनी छत नहीं थी।

ऐसे गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) या मुख्यमंत्री आवास योजना से जोड़ा जा रहा है। सर्वे में मिले पात्र परिवारों को जल्द से जल्द पक्का मकान देने की कवायद तेज कर दी गई है।

आवास निर्माण के लिए जारी होगी किस्त

प्रशासन का लक्ष्य है कि चयनित परिवारों को बिना किसी देरी के आवास निर्माण की पहली किस्त जारी कर दी जाए। आवास योजना के तहत मिलने वाली इस धनराशि से ये गरीब परिवार अपना पक्का आशियाना बना सकेंगे।

अधिकारियों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि आवास निर्माण का पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जाए और इसमें कोई बिचौलिया शामिल न हो। यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।

आयुष्मान कार्ड की स्थिति: 70 प्रतिशत को मिला लाभ, 30 फीसदी प

गरीब परिवारों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत योजना एक महत्वपूर्ण हथियार है। जीरो पावर्टी योजना के तहत चिह्नित 21,523 परिवारों को आयुष्मान गोल्डन कार्ड से भी संतृप्त किया जाना है।

प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार, इन सत्यापित परिवारों में से लगभग 70 प्रतिशत लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड सफलतापूर्वक बनाए जा चुके हैं। ये परिवार अब 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में करवा सकते हैं।

बाकी 30% के लिए विशेष शिविर का आयोजन

हालांकि, अभी भी लगभग 30 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जो तकनीकी कारणों या दस्तावेजों की कमी के चलते आयुष्मान कार्ड से वंचित हैं। प्रशासन ने इस कमी को दूर करने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है।

गांव-गांव में कैंप लगाकर पंचायत सहायकों की मदद से बचे हुए लोगों की ई-केवाईसी (e-KYC) पूरी की जा रही है। अगर आपका कार्ड अभी तक नहीं बना है, तो आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर अपना नाम लिस्ट में चेक कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें: फ्री लोन! पीएम मुद्रा योजना से 10 लाख तक का स्वरोजगार लोन, अभी आवेदन करें

वित्तीय वर्ष 2025-26 की तैयारी: शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने

प्रशासनिक मशीनरी अब नए वित्तीय वर्ष 2025-26 (Financial Year 2025-26) को ध्यान में रखकर काम कर रही है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जिन लाभार्थियों का सत्यापन हो चुका है, उन्हें इस नए वित्तीय वर्ष में बिना किसी रुकावट के लाभ मिलना शुरू हो जाए।

विशेष रूप से पेंशन भुगतान के लिए सूची में शामिल लाभार्थियों का अंतिम बार फिर से सत्यापन किया गया है, ताकि बजट आवंटन में कोई विसंगति न आए। वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक ही योजना का पैसा पहुंचे, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

समयबद्धता पर अधिकारियों का जोर

सभी विकासखंड अधिकारियों (BDO) और ग्राम सचिवों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जीरो पावर्टी योजना के तहत चल रहे कार्यों को एक निश्चित टाइमलाइन के भीतर पूरा किया जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

प्रशासनिक अमला पूरी मुस्तैदी के साथ इन 21 हजार से अधिक परिवारों को सरकारी योजनाओं के जाल में सुरक्षित रूप से पिरोने का प्रयास कर रहा है, जिससे वे मुख्यधारा से जुड़ सकें।

डीपीआरओ का बयान: सभी चिन्हित लाभार्थियों को तय समय में मिलेगा

उन्नाव के जिला पंचायत राज अधिकारी (DPRO) आलोक नाथ सिन्हा ने जीरो पावर्टी योजना की प्रगति पर विस्तृत जानकारी साझा की है। उनके अनुसार, चिह्नित पात्रों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ तेजी से दिया जा रहा है।

डीपीआरओ ने बताया कि कई योजनाओं में शत-प्रतिशत संतृप्तिकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है, जबकि दो प्रमुख योजनाओं में 99 प्रतिशत लाभार्थियों को कवर किया जा चुका है। यह आंकड़े प्रशासन की मेहनत को दर्शाते हैं।

प्रक्रिया को बनाया जा रहा है आसान

डीपीआरओ आलोक नाथ सिन्हा ने यह भी आश्वस्त किया है कि जिन योजनाओं में सत्यापन पूरा होने के बाद पात्र मिले हैं, उन्हें प्रक्रिया की समयबद्धता के अनुरूप लाभार्थी बनाया जा रहा है। कोई भी योग्य व्यक्ति सरकारी लाभ से अछूता नहीं रहेगा।

भले ही आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनने में अभी 30 प्रतिशत लोग वंचित हैं, लेकिन इसे भी जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। कुल मिलाकर, जीरो पावर्टी योजना जिले के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बन गई है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य गरीब और वंचित परिवारों की पहचान कर उन्हें आवास, पेंशन और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सरकारी योजनाओं का लाभ देना है।

उन्नाव में दो चरणों में हुए सर्वे के दौरान शुरुआत में 25,925 परिवारों को शामिल किया गया था, लेकिन अंतिम सत्यापन के बाद केवल 21,523 परिवार ही पात्र पाए गए हैं।

जी हां, जीरो पावर्टी सर्वे में शामिल 60 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे सभी बुजुर्ग जो पहले वंचित थे, उन्हें अब शत-प्रतिशत वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा।

लाभार्थियों की सूची ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध है। इसके अलावा आप अपने पंचायत सहायक या ग्राम प्रधान के माध्यम से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं।

प्रशासन के अनुसार, चयनित 21,523 परिवारों में से 70 प्रतिशत लोगों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं, जबकि शेष 30 प्रतिशत को संतृप्त करने का कार्य अभी जारी है।

बिल्कुल, इस योजना के तहत चिह्नित अति निर्धन और आवासहीन परिवारों को पक्का मकान देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

नए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पेंशन और अन्य योजनाओं के लाभार्थियों का फाइनल सत्यापन कर लिया गया है ताकि बजट आवंटन और लाभ वितरण में देरी न हो।

नहीं, प्रशासन ने दो चरणों में जमीनी सत्यापन किया है, जिसमें लगभग 4402 परिवारों को अपात्र घोषित कर लिस्ट से बाहर कर दिया गया है।

डीपीआरओ ने आश्वस्त किया है कि जो भी परिवार सत्यापन के बाद पात्र मिले हैं, उन्हें प्रक्रिया की समयबद्धता के अनुसार शत-प्रतिशत लाभार्थी बनाया जाएगा।

फिलहाल इसके लिए ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं सर्वे किया गया है। यदि आपका नाम छूट गया है, तो आप अपने ग्राम विकास अधिकारी (VDO) से संपर्क कर आवेदन की जानकारी ले सकते हैं।

हां, सरकारी पोर्टल और ब्लॉक कार्यालय पर सत्यापित लाभार्थियों की आधिकारिक सूची (PDF) फॉर्मेट में उपलब्ध कराई जा रही है।

इस विशेष अभियान के अंतर्गत उन्नाव जिले की कुल 1037 ग्राम पंचायतों में सघन सर्वे किया गया है, ताकि कोई भी गांव अछूता न रहे।